(निर्मलजीत कौर, जे.)

निर्मलजीत कौर जे.के सम्मुख

मोहिंदर सिंह और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

राजा राम और अन्य प्रतिवादीगण

एफ. ए. ओ. No.5703

17 अक्टूबर, 2019

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-मोटर दुर्घटना-मृत्यु मामला-न्यायाधिकरण ने केवल बिना किसी दोष के दायित्व के तहत मुआवजा दिया-दावेदार, जो अविवाहित नाबालिग बहन है-बीमाकर्ता ने मृतक पर निर्भर नाबालिग की याचिका पर दायित्व का विरोध किया-माना, बीमाकर्ता का तर्क अपमानजनक होने के कारण अस्वीकृत होने योग्य है-नाबालिग एक अनाथ है-उसकी देखभाल करने वाला एकमात्र व्यक्ति मृत भाई था, जो अविवाहित था-अन्य सभी भाई-बहन पहले से ही विवाहित थे-इस प्रकार, वह पूरी तरह से मृतक पर निर्भर थी-नाबालिग होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह काम कर रही थी-इस प्रकार, लगभग मृतक पर एक अविवाहित आश्रित बेटी की तरह माना जाता है, जो अपने जीवन में पिता के समान थी-पुरस्कार में संशोधन और मुआवजा दिया गया।

यह तर्क कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह आश्रित नहीं थी, वर्तमान मामले के तथ्यों में एक अपमानजनक तर्क होने के नाते खारिज किए जाने योग्य है।अपीलार्थी नं. 6 के माता-पिता नहीं थे। न तो उसके पिता और न ही उसका भाई जीवित थे। वह एक अनाथ है। उसकी देखभाल करने वाला एकमात्र व्यक्ति मृतक था जो अविवाहित था, जबकि अन्य सभी भाई-बहन शादीशुदा थे और उनको अपने-अपने परिवारों की देखभाल करनी थी। इस प्रकार, इसके बावजूद, वह अपने अविवाहित भाई पर 100 % निर्भर थी। वह केवल 14 वर्ष की थी, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह काम कर रही थी और अपनी देखभाल करने में भी सक्षम थी और क्या वह दिन में दो बार भोजन करने की स्थिति में भी थी। किसी जीवित माता-पिता की अनुपस्थिति में, वह लगभग मृतक पर एक अविवाहित आश्रित बेटी की तरह थी। मृतक उसके जीवन में एक पिता समान था।

(पैरा 9)

आगे यह कहा कि, यह न्यायालय प्रतिवादी No.3/Insurance कंपनी के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क को सुनकर हैरान है, जिसमें नाबालिग अनाथ बहन की पर निर्भरता को चुनौती दी गई है।

तदानुसार, वर्तमान अपील को निम्नलिखित रूप में पुरस्कार को संशोधित करके अपीलार्थी संख्या 6 के लिए अनुमति दी गई है।

(पैरा 10)

दर्शन L.Gulati, अधिवक्ता

अपीलार्थियों के लिए।

डी. के. प्रजापति, अधिवक्ता

उत्तरदाता No.3-Royal सुंदरम गठबंधन बीमा के लिए।

उत्तरदाता Nos.4,7 और 8 पूर्व पक्षीय आदेश दिनांक 30.04.2015।

सुखदीप सिंह, प्रतिवादी संख्या 5 के लिए अधिवक्ता।

राजबीर सिंह, संजीव गोयल के वकील,अधिवक्ता

उत्तरदाता No.6-HDFC ERGO सामान्य बीमा के लिए।

निर्मलजीत कौर, जे. मौखिक

सीएम-15822-सीआईआई-2014

(1) अनुमति दी, जैसा कि प्रार्थना की गई थी।

मुख्य मामला

(1) वर्तमान अपील दावेदारों द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, करनाल (संक्षेप में, न्यायाधिकरण) द्वारा पारित दिनांक 19.03.2014 के निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें बिना किसी गलती के दायित्व के तहत केवल 50,000/- की राशि दी गई थी।

(2) शुरुआत में, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने उनके दावे को अपीलार्थी संख्या 6 यानी अविवाहित बहन, जो दुर्घटना के समय 14 वर्ष की थी, तक सीमित कर दिया।

(3) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता Nos.1 से 5 तक की अपील को दबाए बिना खारिज कर दिया जाता है।

(4) प्रत्यर्थी No.3-Insurance कंपनी के विद्वान वकील ने अपीलार्थी संख्या 6 के दावे का जोरदार विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी No.6- पूनम देवी उर्फ गुंड्री नाबालिग मृतक पर निर्भर थी। मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा रखा गया था सरला **वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और मोहिंदर सिंह और अन्य बनाम राजा राम और अन्य**

(निर्मलजीत कौर, जे.)

अन्य 1 और श्रीमती मंजुरी बेरा बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस

कंपनी लिमिटेड और अन्य 2, माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा प्रदान किए गए

अमोलीराम और अन्य बनाम सियाराम और अन्य मामले में न्यायालय 3, और

प्रदीप के मामलों में इस न्यायालय की विद्वान एकल पीठ (ओं) द्वारा प्रस्तुत किया गया

प्रदीप बनाम धरमबीर और अन्य 4, कश्मीर कुमार और अन्य बनाम मोहन सिंह और अन्य 5 और बिजेंद्र वगैरा बनाम रणबीर सिंह और अन्य, एफ. ए. ओ.-1628-2013, ने 19.09.2017 पर चुनाव लड़ने का फैसला किया कि चूंकि मृतक अलग रह रहा था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक अपनी बहन की देखभाल कर रहा था या वह अपने मृत भाई पर निर्भर थी।

(5) सुना है।

(6) प्रतिवादी No.3/Insurance कंपनी के लिए विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट उपरोक्त निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून के साथ कोई विवाद नहीं है। हालाँकि, सभी निर्णय या तो विवाहित बेटों, विवाहित बेटियों, विवाहित भाइयों या विवाहित बहनों से संबंधित होते हैं। उनमें से कोई भी नाबालिग अविवाहित बहन से संबंधित नहीं होता है। इसलिए, निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

(7) वास्तव में, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय,ने केस मैग्मा **जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम @चुहरू राम** और अन्य 6, निम्नलिखित रूप में धारण करने के लिए प्रसन्न थे:-

क्र. स0	मुखिया	मूल्यांकन की गई राशि
1	आमदनी	रु. 4, 000/- प्रति माह (4000 x 12 = 48000 प्रति वर्ष)
2	भविष्य की संभावनाएं	40% (48,000 x 40% = Rs.19,200) Rs.48000 + 19200 = '67,200/-
3	कटौती	60% 60% 67200 का = Rs.40320-67200-40320 = '26880/-
4	गुणक	17

1. 2009 (3) आरसीआर (सिविल) 77

2. 2007 (2) आर. सी. आर. (सिविल) 674

3. 2013 (2) ए. आई. सी. जे. 160

4. 2015 (1) पीएलआर 392

5. 2014 (2) पीएलआर 13

6. 2018 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 333

5	मुआवजा दिया गया	26880 x 17 = रु. 4,56,960 -
6	संपत्ति का नुकसान	Rs.15,000/-
7	अंतिम संस्कार का खर्च	Rs.15,000/-
8	कुल	रुपये. 4,86,960 -
9	न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया मुआवजा	Rs.50,000/-
10	मतभेद	Rs.486960-50,000 = Rs.436960 -

" 8.4.बीमा कंपनी ने प्रस्तुत किया है कि मृतक के पिता और बहन को आश्रित नहीं माना जा सकता है, और यह केवल एक माँ होती है जो अपने बेटे पर निर्भर हो सकती है। इस विवाद को खारिज किया जाना चाहिए। मृतक कुंवारा था, जिसकी माँ उसकी पहले ही मर चुकी थी। मृतक के पिता की आयु लगभग 65 वर्ष और एक अविवाहित बहन थी। मृतक अपनी अल्प आय का एक हिस्सा परिवार को उनके निर्वाह और अस्तित्व के लिए दे रहा था। इसलिए, वे उसके आश्रितों के रूप में मुआवजे के हकदार होंगे।"

(8) यह तर्क है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह आश्रित नहीं थी, वर्तमान मामले के तथ्यों में एक अपमानजनक तर्क होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।अपीलार्थी नं. 6 के माता-पिता नहीं थे। न तो उसके पिता और न ही उसका भाई जीवित थे। वह एक अनाथ है। उसकी देखभाल करने वाला एकमात्र व्यक्ति मृतक था जो अविवाहित था, जबकि अन्य सभी भाई-बहन शादीशुदा थे और उन्हें अपने-अपने परिवारों की देखभाल करनी थी। इस प्रकार, इसके बावजूद, वह अपने अविवाहित भाई पर 100% निर्भर थी। वह केवल 14 वर्ष की थी, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह काम कर रही थी और अपनी देखभाल करने में भी सक्षम थी और क्या वह दिन में दो बार भोजन करने की स्थिति में भी थी। किसी जीवित माता-पिता की अनुपस्थिति में, वह लगभग मृतक पर एक अविवाहित आश्रित बेटी की तरह थी। मृतक उसके जीवन में एक पिता समान था।

(9) यह न्यायालय प्रतिवादी No.3/Insurance कंपनी के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क को सुनकर स्तब्ध है, जिसमें नाबालिग अनाथ बहन की अपने अविवाहित भाई पर निर्भरता को चुनौती दी गई है। तदानुसार, वर्तमान अपील को निम्नलिखित रूप में पुरस्कार को संशोधित करके अपीलार्थी संख्या 6 के लिए अनुमति दी गई है।

(10) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करना

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय मोहिंदर सिंह और अन्य बनाम राजा राम और अन्य के मामले में अदालत

प्रणय सेठी और अन्य 7, एक अकुशल श्रमिक होने के नाते आय का आकलन 4,000/- रुपये प्रति माह किया जाता है और दावेदार 17 के गुणक के साथ-साथ 40 प्रतिशत भविष्य की संभावनाओं के साथ-साथ संपत्ति के नुकसान और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 1,000/- के अनुदान का हकदार है।अब सवाल केवल कटौती का है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि कटौती 50 प्रतिशत की दर से की जानी चाहिए क्योंकि मृतक अविवाहित था, हालाँकि, माता-पिता अभी भी जीवित हैं तो ऐसा ही है।वर्तमान मामले में, केवल एक दावेदार है, लेकिन चूंकि दावेदार एक अविवाहित नाबालिग बहन है जो मृतक पर निर्भर है, इसलिए 60 प्रतिशत की सीमा तक कटौती करना उचित होगा।

(11) इसी को ध्यान में रखते हुए, रुपये की बढ़ी हुई राशि का भुगतान अपीलार्थी संख्या 6 को नीचे दी गई गणना के अनुसार किया जाना चाहिए:-

(12) इस प्रकार, इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति से दो महीने के भीतर अपीलार्थी संख्या 6 को दावा याचिका दायर करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक प्रति वर्ष 6 प्रतिशत ब्याज के साथ रु. 4,36,960 के बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान किया जाए। यदि उक्त राशि का भुगतान दो महीने के भीतर नहीं किया जाता है, तो दो महीने की अवधि की समाप्ति से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ इसका भुगतान किया जाएगा।

(13) इस स्तर पर, न्यायालय अपीलार्थी संख्या 6 की वर्तमान दावा याचिका का विरोध करने के लिए बीमा कंपनी पर भारी लागत लगाने से खुद को रोकता है, इस आधार पर कि उसे पूरी तरह से जानते हुए आश्रित नहीं माना जा सकता है कि वह नाबालिग और अविवाहित लड़की थी।

(14) अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

सुनील चौपड़ा

7 (2017) 16 एससीसी 680

स्पष्टीकरणः– स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके किसी अन्य उददेष्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता हे। सभी व्यवहारिक और अधिकारीक उददेष्यो के लए निर्णय का अग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कायान्वयन के उददेष्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।